

मूक पात्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 277 बेमेतरा, बुधवार 03 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

दरियादिली जान पर पड़ी भारी! बच्ची की जान बचाने नदी में कूदे 5 लोग

कुरनूल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में इंसानियत और बहादुरी की एक दर्दनाक मिसाल देखने को मिली। तुंगभद्रा नदी में फिसलकर गिरी एक नाबालिग लड़की को बचाने के लिए पांच लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। बच्ची को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उसे बचाने वाले पांचों लोग तेज बहाव में बह गए। पुलिस के अनुसार, सभी के डूबने की आशंका है और उनकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 4:30 बजे मंत्रालयम क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के किनारे यह हादसा हुआ। एक नाबालिग लड़की नदी किनारे पैर धो रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर नदी में गिर गई। कुछ ही पलों में वह तेज धारा में बहने लगी। लड़की को बहता देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। उसकी जान बचाने के लिए पहले एक व्यक्ति नदी में कूदा, फिर दूसरा और देखते ही देखते कुल पांच लोग बचाव के लिए पानी में उतर गए।

कंटेनर से टकराई कार, तीन की मौत, गाड़ी काटकर निकाले शव

आगरा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। बिहार से राजस्थान का रही एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा कंटेनर के भीतर तक घुस गया और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रास जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार रात करीब 1:45 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 36+950 पर हुआ। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि लंबी यात्रा के दौरान चालक को झपकी आ गई, जिसके चलते कार अनियंत्रित होकर कंटेनर से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग दहल उठे। कार की कंडक्टर साइड पूरी तरह चकनाचूर हो गई और वाहन कार्टर में फंस गया। कार चला रहे मोहम्मद सोएव अपने साथियों के साथ राजस्थान के चुरू जिले की ओर जा रहे थे।

भारत की राजनीति में घुसने की साजिश रच रहा पाकिस्तान

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार सख्त होती कार्रवाई से बौखलाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब एक नई रणनीति के तहत भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, आईएसआई ने अपने समर्थक नेटवर्क और ओवर ग्राउंड वर्कर्स को मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सके और आतंकी तंत्र को नया आवरण प्रदान किया जा सके। सूर्यों के मुताबिक, हाल के महीनों में हुई कई गिरफ्तारियों और पूछताछ के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ संदिग्ध तत्व राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने का दावा कर रहे थे। जांच एजेंसियां इस पहलू की गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं।

वेदांता ग्रुप पर ईडी का छापा

फाउंडर अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

नई दिल्ली/ एजेंसी

इस वक्त की बड़ी देश के औद्योगिक घराने से आई है। देश की प्रमुख बिजनेस कंपनी वेदांता ग्रुप पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए से जुड़े एक मामले में की गई है, जिसकी जांच चल रही है। वेदांता के खिलाफ यह तलाशी सोमवार से ही जारी है। मामले या तलाशी के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी या ईडी की तरफ से आधिकारिक जवाब का इंतजार है। वेदांता के खिलाफ तलाशी अभियान तकंदीय एजेंसी ने एफईएमए एक्ट के तहत इस मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी के खिलाफ जांच के दौरान शुरू की। वेदांता के खिलाफ यह जांच कंपनी अपने सिक्नोइड लेनदारों से एक बड़े डीमर्जर प्लान के लिए मंजूरी मिलने के लगभग एक महीने बाद शुरू हुई है, जिसके तहत कंपनी की 5 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा जाना है। बता दें कि फेमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर निगरानी रखना होता है। ईडी एफईएमए का इस्तेमाल उन मामलों की जांच के लिए करता है जहां उसे संदेह होता है कि किसी व्यक्ति या कंपनी ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें अधिकतर ऐसे मामले शामिल होते हैं जैसे अवैध रूप से विदेश में धन हस्तांतरण करना, हवाला, विदेश में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करना, या विदेशी निवेश से संबंधित नियमों का पालन न करना। बता दें कि वेदांता ग्रुप का नाम पहले भी विदेशी मुद्रा मामलों में नियामक जांच के दायरे में आ चुका है। वर्ष 2004 में प्रवर्तन निदेशालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और उसके तीन प्रमोटर निदेशकों को एफईआरए और फेमा के नियमों के उल्लंघन का



वेदांता ने कहा- जांच में पूरा सहयोग करेंगे

वेदांता ने सर्व ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी के बयान में कहा गया, हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और आवश्यक सभी दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। वेदांता सभी लागू कानूनों और नियामकीय प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि मामला पिछला जांच प्रक्रिया में है, इसलिए इस समय इससे अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एफईएमए से जुड़ी यह जांच ऐसे समय में सामने आई है जब वेदांता अपने डीमर्जर और संभावित नई लिस्टिंग्स की तैयारी कर रही है। ऐसे में जांच के निष्कर्षों पर निवेशकों, शेयर बाजार और जियामक संस्थाओं की करीबी नजर बनी रहेगी। हालांकि कंपनी ने कानूनों के पालन और जांच में सहयोग का भरपूर जवाब है, लेकिन आने वाले दिनों में ईडी की जांच से जुड़े निष्कर्ष बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।

दोषी पाया था और कंपनी तथा उसके निदेशकों पर जुर्माना लगाया था। वहीं अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ के सक्ति में पावर प्लांट में बाँयरन फटने के मामले में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया था। सक्ती जिला स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में अनिल अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। जबकि पिछले महीने (मई 2026) बुला

सिंचाई प्रभाग ने ओडिशा में भेडेन नदी/नहर से बिना अनुमति के पानी निकालने के आरोप में वेदांता एल्युमीनियम पर ₹233.11 करोड़ का जुर्माना लगाया था। वेदांता ग्रुप भारत की सबसे बड़ी प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। भारत की कुल ज़रूरत का लगभग 81% उत्पादन यही ग्रुप करता है। कंपनी केयरन इंडिया की मदद से कच्चे तेल का उत्पादन करती है। वेदांता ग्रुप ने भारत में अगले कुछ सालों में लगभग 2 लाख करोड़ का भारी निवेश करने की योजना बनाई है।

सलीम डोला ड्रग्स केस में ईडी का एक्शन, मुंबई-गुजरात में 20 ठिकानों पर छापेमारी



अन्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के करीबी और इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर सलीम इस्माइल डोला के 20 ठिकानों पर श्वक की बड़ी कारवाही चली। इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कारवाही करते हुए ईडी सलीम इस्माइल डोला के साथ उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गयी है. यह कारवाही मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर की गयी है. ईडी के मुताबिक तुरकियों से भारत वापस लाए गए तस्कर मोहम्मद सलीम डोला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क मामले में यह छापेमारी चल रही है. जांच एजेंसियों के मुताबिक अभी हाल ही में तुर्की से भारत लाए गए सलीम डोला का संबंध अन्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के नेटवर्क से भी रहा है और वह काफी समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों के कारोबार में सक्रिय था. ईडी के राडार पर इस बाने में इस्तेमाल होने वाले कैमिकल्स के सलावार, कारोबार से जुड़े बिजौलिंग, सिंथेटिक ड्रग्स मेफेक्शन (एमडी) के निर्माता और तस्कर, हवाला अपरेटर तथा ड्रग्स के पैसे से खरीदी हुई बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोग शामिल हैं. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था और हजारों करोड़ रुपये के ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ है. यह जांच प्रवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शुरू की गई है. ईडी को जांच के दौरान एक बेहद संगठित और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के सबूत मिले हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि अपराध से अर्जित धन को हवाला चैनलों के जरिए इधर-उधर भेजा जाता था ताकि उसकी असली पहचान छिपाई जा सके. छापेमारी के दौरान दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं.

टिवशा शर्मा केस

समर्थ और गिरीबाला सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। भोपाल के चर्चित टिवशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जज गिरीबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान दोनों आरोपियों को अन्य कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार, सोमवार (2 जून) को रिमांड समाप्त होने के बाद दोनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। कोर्ट रूम की कार्यवाही के दौरान माहौल उस समय गरमा गया जब दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुनवाई में आरोपी गिरीबाला सिंह ने आरोप लगाया कि दिवशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की थी। इस आरोप पर अधिकवा अनुराग



श्रीवास्तव ने कहा कि जबलपुर कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी पुष्टि निकलवाकर जांच कर ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थ सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे उस समय कोर्ट परिसर में कहां मौजूद थे. मामले की जांच के दौरान समर्थ सिंह और उनकी मां गिरीबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के सभी आरोपों को खारिज किया है। दोनों का कहना है कि दिवशा के साथ उनके संबंध सामान्य थे और लगाए गए आरोप निराधार हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयानों का उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ उतरंगी सड़कों पर 6 जून को भारत लौट रहे अभिजीत दीपके

नई दिल्ली । देश में नीट परीक्षा को लेकर मने सिपासी घमासान और छात्रों के आक्रोश के बीच अब सोशल मीडिया की जंग सीधे देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट की एक हिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर आंधी की तरह उमरी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अब दिल्ली में एक बड़े और व्यापक आंदोलन का बिगुल फूंकने जा रही है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इसके संस्थापक और चर्चित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके आगामी 6 जून को अमेरिका से भारत लौट रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंतौअर्स से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है, जिसके बाद से ही खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि आखिर अभिजीत दीपके के आवाक भारत आने और इस कथित आंदोलन के पीछे का मुख्य एजेंडा क्या है? इसका खुलासा खुद अभिजीत ने अपने वीडियो में किया है।

सड़क पर उतरी ममता बनर्जी

सुवेंदु पर बोला हमला,मुझे गिरफ्तार कर लो-ममता....

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं पर एक-एक करके कई हमलों के बाद बंगाल की सियासत गरमा गई है। भड़की हुई दीदी यानी बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है। ममता दीदी ने कहा कि भले ही मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन मैं जनता के बीच बैठूंगी ही...दरअसल बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन कोलकाता के ऐतिहासिक रानी रासमणि एवेन्यू पर



शुरू हो गया है। यहां ममता बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर हुए हालिया हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गई हैं। धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ममता ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर

पुष्पांजलि अर्पित की और अपने हाथों में भारत के संविधान की एक प्रति लेकर मार्च किया। उन्होंने सीधे तौर पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि टीएमसी के नेताओं को डराकर या उनके सुरक्षा कवच को हटाकर पार्टी को कमजोर नहीं किया जा सकता। टीएमसी का आरोप है कि जब अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चुनावी हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे उस दौरान उनके काफिले पर ईंटों, पत्थरों और अंडों से हमला किया गया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए।

कुशीनगर में गरजे सीएम योगी

यूपी में अब कट्टा नहीं,सीधे मिसाइल बनती है-योगी.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने जनपदवासियों को विकास की एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कुल 424 करोड़ रुपये की लागत वाली 278 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और जसता के कल्याण के लिए प्रदेश के खजाने का मुंह पूरी तरह खुला हुआ



है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर केवल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जनसभा में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला

बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय सूबे में कट्टा और बम बनाए जाते थे, जिससे केवल दंगे और बेरोजगारी फैलती थी। लेकिन आज का नया उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब यहाँ अवैध कट्टे नहीं बल्कि डिफेंस कॉरिडोर में सीधे मिसाइलें बनती हैं। जिसे दामने पर पड़ोसी देश पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कोई भी पर्व-त्योहार बिना दंगों के नहीं मनता था, लेकिन आज अपराधियों में खौफ के चलते कोई दंगा करने की सोच भी नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए।

रोकी गई केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ मार्ग पर भी संकट, भारी बारिश के कारण रास्ते में फंसे यात्री

देहरादून । उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने चारधाम यात्रा पर असर डालना शुरू कर दिया है। खराब मौसम, भूस्खलन और सड़कों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भी हजारों श्रद्धालु घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे यात्रा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है।

हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र है-सुप्रीम..

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उन फैसलों को पलट दिया है, जिन फैसलों के मुताबिक शादीशुदा बेटी अपने माता-पिता के परिवार में नहीं आती है और इसलिए उसे अनुकंपा लाभ नहीं मिल सकता है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अग्रुथे की पीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को बाहर रखना संविधान के समानता सिद्धांत के खिलाफ है। फैसले में कहा है कि माता-पिता के ना रहने पर उनपर आश्रित विवाहित पुत्री अनुकंपा रोजगार की पात्र है. सुप्रीम कोर्ट ने साफसाफ कहा है कि अगर शादीशुदा बेटी अन्य सभी शर्तें पूरी करती है तो उसका दावा सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने



इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन फैसलों को पलटते हुए कहा की सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति या कल्याणकारी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की सभी शर्तें पूरी करती है तो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि माता-पिता के ना रहने पर उनपर आश्रित विवाहित पुत्री अनुकंपा रोजगार की पात्र है.

सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे बीजापुर के सुदूर गांव कोण्डापल्ली

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ: ग्रामीणों से किया संवाद...

■ सुशासन का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंच रही सरकार, योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने स्वयं पहुंचे मुख्यमंत्री

रायपुर/ संवाददाता

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आग बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित

जनचौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं, योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान का प्रयास कर रही



और किसी भी जरूरतमंद को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। इसी भावना के साथ सरकार स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान का प्रयास कर रही

है। जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों से चर्चा कर योजनाओं के प्रभाव और उनके अनुभवों की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे और आमजन को शासन की संवेदनशीलता का अनुभव हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनका समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा क्षेत्र के विकास में कोई भी गलती नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई धारा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न, कलेक्टर महोबे ने नागरिकों का किया आभार

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जनगणना 2027 हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जो केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि भविष्य के भारत और हमारे राज्य व जिले के विकास की ठोस नींव तैयार करने का कार्य करेगा। भारत की जनगणना 2027 का कार्य राज्य में दो चरणों में संपादित किया जा रहा है। प्रथम चरण (फेस-1) यथा मकानसूचीकरण एवं मकानों के गणना का फ़ील्ड कार्य 01 मई 2026 से प्रारम्भ होकर 30 मई 2026 को सभ्यतापूर्वक संपादित हो गया है। द्वितीय चरण, जनसंख्या गणना का कार्य फरवी 2027 में संपादित किया जाएगा। प्रथम चरण मकानसूचीकरण का कार्य, द्वितीय चरण जनसंख्या गणना कार्य के लिए एक प्रेम प्रदान करती है, जिससे कि द्वितीय चरण, जनसंख्या गणना कार्य के दौरान कोई भी मकान एवं उसमें रहने वाले परिवार गणना से न छूटे। प्रथम चरण मकानसूचीकरण कार्य के दौरान जिले के सभी ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में



प्रारणकों के द्वारा घर-घर जाकर प्रत्येक मकान एवं उसमें निवासरत परिवारों से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 33 प्रश्न जो कि मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित थी, की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से संकलित की गई। अब यह जानकारी भारत सरकार के सर्वर में सुरक्षित रख ली गई है। प्रथम चरण मकानसूचीकरण कार्य जिला के समस्त तहसीलों, ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में कुशलता एवं शांतिपूर्वक संपादित किया गया। इस दौरान

जिला के समस्त क्षेत्रों को पूर्ण रूप से कवर किया गया एवं कोई भी क्षेत्र गणना कार्य से नहीं छूटा है। प्रणकों के द्वारा घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करने के दौरान जिले के निवासियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है।

जिले के आम नागरिकों के द्वारा जनगणना से संबंधित जो भी व्यक्तिगत जानकारी दी गई है, वह जनगणना अधिनियम

1948, तथा जनगणना नियमावली 1990, के प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। संकलित किए गए इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा एवं भारत सरकार के द्वारा सम्पूर्ण जनगणना प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यथोचित समय पर इन आंकड़ों को जारी किया जाएगा।

जांजगीर चाम्पा जिले में जनगणना 2027 प्रथम चरण का कार्य 12 नगरीय निकाय एवं 9 तहसीलों के अंतर्गत 429 ग्रामों

राजस्व की लूट, अवैध खनन में छूट!! खनिज विभाग का बढ़ावा देना या फिर खनन माफियाओं से चढ़ावा लेना?

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक

पत्रिका

जिले में अवैध खनन को लेकर

एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्षेत्र में लंबे समय से जारी खनन गतिविधियों और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं तेज हैं। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की कथित लापरवाही और छिले रखैये के कारण प्रशासन को राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उठ रहे आरोपों के अनुसार, सारंगढ़ में पदस्थ खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर असंतोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बोते दो वर्षों में जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। इस दौरान खनिज संसाधनों के दोहन और अवैध रूप से खदान संचालन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। आरोपों के केंद्र में सहायक खनिज अधिकारी बजरंग



पैकरा की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि जब जिले में खनिज विभाग में हीरादास भारद्वाज पदस्थ थे, तब अवैध खनन पर नियंत्रण अपेक्षाकृत सख्त माना जाता था। वहीं अब लोगों का आरोप है कि खनन माफियाओं के हासले बूढ़े हैं और कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन तथा परिवहन जारी है। हालांकि इन आरोपों पर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर प्रभावी निगरानी, लीज की शर्तों की समीक्षा, भंडारण अनुमति और रॉयल्टी संबंधी प्रक्रियाओं की कड़ाई से जांच की जाती, तो अवैध गतिविधियों में

कमी लाई जा सकती थी। विभाग की कार्रवाई रिपोर्टों में परिवहन पर छापेमारी और जब्ती की बातें सामने आती हैं, लेकिन आरोप यह भी हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहे कथित अवैध खनन पर अपेक्षित सख्ती दिखाई नहीं देती। मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व जिलाधिकारी डॉ. संजय कनौजे के कार्यकाल में अवैध खनन संबंधी शिकायतें उनके सज्ञान में लाई गई थीं। वहीं वर्तमान जिला प्रशासन से भी लोग कार्रवाई की उम्मीद लगाए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर यह सवाल लगातार उठ रहा है कि यदि अवैध खनन की शिकायतें और गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो आखिर जिम्मेदार विभागीय अमला इस पर प्रभावी रोक लगाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा? पिछले जिले में अवैध खनन को लेकर चर्चाएं और आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखा जा रहा होगा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग इन गंभीर सवालों पर क्या रुख अपनाते हैं और अवैध खनन तथा राजस्व नुकसान के आरोपों पर क्या ठोस कार्रवाई सामने आती है।

योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा



सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रागतिरत कार्यों, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन और सुशासन तिहार शिविर से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में की गई। इसमें पुल पुलिस, सड़क, विद्युत, पेयजल, वन अधिकार पत्र, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, नक्शा बटनकन, राशन कार्ड,

जगदलपुर में नशे के कारोबार पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 हजार रुपये से अधिक की नशीली कैप्सूल जब्त

जगदलपुर /मूक

पत्रिका

बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 54,400 रुपये मूल्य की 136 नग नशीली कैप्सूल जब्त की गई हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बोधघाट थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे एक युवक नशीली कैप्सूल बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के



पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दखिा दी। रैड कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदेही युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। पृष्ठताछ में उसने अपना नाम बंटू चौहान (27 वर्ष), निवासी अडावाल खासपारा बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से Pyeevon Spas Plus Tramadol

HCL Capsules के 17 पते, कुल 136 नग कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 54,400 रुपये बताई गई है। आरोपी नशीली दवाओं के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(क) के तहत अपराध दर्ज कर मादक

पदार्थ जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष एनडीपीएस न्यायालय जगदलपुर में पेश किया। बस्तर पुलिस ने कहा है कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

इस कार्रवाई में निरीक्षक टामेश्वर चौहान, उप निरीक्षक ललित नेगी, लोकेश्वर नाग, सहायक उप निरीक्षक सतीश श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक अहिलेश नाग, सुनील मगर, व्यास नारायण, डोलामनी भोई, लखेश्वर बघेल सहित थाना बोधघाट के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



कहा कि रायगढ़ के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को

आम जनता तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जन्मदिवस समारोह में श्रमिकों ने केक काटने के

साथ एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिला श्रमिकों ने भी बड़-

लोधिया के सील पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म बोर्ड लगाने से विवाद, विरोध के बाद हटाया गया बोर्ड...!

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक

पत्रिका

डभरा (लोधिया) स्थित यशोदेव किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप एक बार फिर चर्चा में आ गया है। डीजल अनियमितता के मामले में प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप सील किए जाने के बाद अब वहां +स्टॉक खत्म+ का बोर्ड लगाए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया।

जानकारी के अनुसार प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सील करते हुए पहुंच मार्ग पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई थी, ताकि आम लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सके कि उक्त पेट्रोल पंप से फिलहाल ईंधन उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन इसी बैरिकेडिंग में पंप संचालक द्वारा +स्टॉक खत्म+ का बोर्ड लगा दिया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। स्थानीय सरपंच और



जनप्रतिनिधियों का कहना था कि जब पेट्रोल पंप प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सील किया गया है, तब +स्टॉक खत्म+ का बोर्ड लगाना लोगों को गुमराह करने जैसा है। उनका आरोप था कि इससे आम जनता के बीच गलत संदेश जा रहा था और सील कार्रवाई की

वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास दिखाई दे रहा था। मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद जिला खाद्य अधिकारी गणेश कुर्ते ने स्पष्ट किया कि सील किए गए पेट्रोल पंप में +स्टॉक खत्म+ का बोर्ड लगाया जाना अनुचित है। जानकारी मिलने पर पंप

संचालक को तत्काल बोर्ड हटाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद बोर्ड हटा लिया गया। प्तिहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि सील पेट्रोल पंप पर आखिर +स्टॉक खत्म+ का बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी...?

शहीदों को श्रद्धांजलि, लोकनृत्य और देशभक्ति गीतों से सजा समारोह; बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियानों के साथ जनसेवा में भी निभा रही अहम भूमिका

41वें स्थापना दिवस पर 85वीं वाहिनी ने दिखाई देश की सांस्कृतिक एकता

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। नयापारा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 85वीं वाहिनी ने सोमवार को अपना 41वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया। दिनभर चले कार्यक्रमों के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और शाम को आयोजित सांस्कृतिक संस्था में जवानों ने देश की विविध संस्कृति को मंच पर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई।

कमांडेंट सुनील कुमार राही सहित अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया। इसके बाद कमांडेंट ने क्वार्टर गार्ड पर सलामी ग्रहण की। 85वीं वाहिनी की स्थापना 1 जून 1985 को राजस्थान के अजमेर स्थित सीआरपीएफ समूह केंद्र में हुई थी। स्थापना के



बाद वाहिनी ने अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम, त्रिपुरा और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद, उग्रवाद और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। वर्ष 2008 से बीजापुर जिले में तैनात यह वाहिनी नक्सल विरोधी अभियानों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही सिविक एक्शन कार्यक्रम, चिकित्सा

शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और जनहितकारी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों के बीच विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास भी कर रही है। सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच बड़े सहयोग का असर क्षेत्र के विकास पर भी दिखाई दे रहा है। दूर-दराज के इलाकों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और बिजली जैसी सुविधाएं लगातार पहुंच रही हैं। स्थाना दिवस के अवसर पर वाहिनी मुख्यालय के



अलावा पेढ़ापारा, पुसनार, हिरोली, डुमरीपालनार, कावड़गांव और मुदवंछे स्थित कंपनी मुख्यालयों में भी खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। जवानों ने राजस्थानी लोकनृत्य, ओडिशा का संबलपुरी नृत्य, असम का बिहु, पंजाब का भांगड़ा, दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक

नृत्य तथा बस्तर की पारंपरिक लोक संस्कृति की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। देशभक्ति गीतों और नाट्य प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक एक ही मंच पर सिमट आई हो। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप महानिरीक्षक (ऑपरेशन) रेंज बीजापुर बी.एस. नेगी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न

वाहिनियों के कमांडेंट, उप कमांडेंट, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अतिथियों ने 85वीं वाहिनी के 41वें स्थापना दिवस पर कमांडेंट सुनील कुमार राही, अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं देते हुए आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों और जनहित के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

1985 में हुई थी स्थापना, 2008 से बीजापुर में तैनात

85वीं वाहिनी का गठन 1 जून 1985 को अजमेर में हुआ था। वर्ष 2008 से यह वाहिनी बीजापुर में तैनात है। नक्सल विरोधी अभियानों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित कर जनता और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास बढ़ाने का काम कर रही है।

संपादकीय

भीषण गर्मी में बढ़ता एसी का उपयोग जहां राहत देता है, वहीं तकनीकी खामी और लापरवाही इसे गंभीर खतरे में भी बदल सकती है। इसमें दोराय नहीं कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने मानव जीवन की राह को आसान बना दिया है। मगर तकनीक तभी सुविधाजनक होती है, जब उसे कौशल, संवेदनशीलता और सतर्कता के दायरे में रखा जाए। जरा-सी

लापरवाही पर यह सुविधा कब जोखिम में बदल जाए, इसका आभास भी नहीं हो पाता है। बीते बुधवार की रात को दिल्ली के हौजखास इलाके में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसमें एयर कंडीशनर यानी एसी में विस्फोट से लगी आग की वजह से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी धनेंद्र कुमार की जान चली गई।वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एसी में

विस्फोट किन कारणों से हुआ, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सवाल है कि जिन उपकरणों को घरों में सुविधा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनमें तकनीकी खराबी से पैदा होने वाले खतरे से सुरक्षा की जम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत नहीं है?गौरतलब है कि हर साल गर्मी में एयर कंडीशनर की वजह

से हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले एक माह में देश भर में एसी में विस्फोट या आग लगने से मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निस्संदेह इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर एसी के मामले में ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, क्योंकि इससे और भी कई तरह के जोखिम होते हैं।मसलन, बहुत ठंडे

कमरे से अचानक तेज गर्मी में जाने से शरीर का तापमान बदल जाता है, जिससे मस्तिष्काघात का खतरा बढ़ जाता है। एयर कंडीशनर कमरे की नमी को सोख लेता है, जिससे सांस और त्वचा संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, इस उपकरण से गैस का रिसाव होने पर बंद कमरे में दम घुटने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। यानी किसी भी तकनीकी संसाधन के

उपयोग के साथ ही उनके संचालन के लिए एक मुकम्मल प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है।जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे उपकरणों में तकनीकी खराबी की वजह से कोई हादसा न हो, इसके लिए सरकार की ओर से स्पष्ट नीति एवं नियम बनाए जाएं, ताकि इनके निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

रील्समय सब जग जानी

(उमेश चतुर्वेदी)

पत्रकारिता के जब भी नए माध्यम सामने आए, पुराने माध्यम के ख़ात्मे की आशंका जताई जाती रही। हालांकि नए माध्यम के किंचित गुणों के साथ प्रतियोगिता और साम्यता बरतते हुए पुराने माध्यम ने जहां खुद को ज्यादा प्रतियोगी बनाया। हर नए माध्यम के अवतार और विकास के मूल में नई तकनीक रही है।

सियाराम मय सब जग जानी...तुलसी के लिए समूचा विश्व ही श्रीराम और सीता की तरह रहा। आज की पत्रकारिता पर जिधर भी नजर फ़िराएँ, कुछ उसी तरह टीवी मय हो लगती है। लगता नहीं कि मीडिया की की दुनिया में अखबार भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं, रेडियो भी है और सबसे अहम इंटरनेट भी है। दो सौ साल की हिंदी पत्रकारिता का इतिहास गरिमा के सोपानों से भरा हुआ है। नवजागरण को बढ़ावा देने, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन मूल्यों की स्थापना में हिंदी पत्रकारिता ने महती भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से उपजी हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का माध्यम भी बनी, लेकिन दो सौ साल की यात्रा के उपरांत बाद के वर्षों के उसके इतिहास को देखते हैं तो वह सिर्फ टीवीमय नजर आती है, टीवी से भी आगे बढ़कर वह रीलमय नजर आती है। छापे से शुरू हिंदी पत्रकारिता का यह रूप छापे और रेडियो की उपस्थिति के बावजूद आज वह रील्स के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। टेलीविजन तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद की जब तकनीक के सहारे टीवी की दुनिया में चुपके से रील्स ने दखल देनी शुरू की तो स्थितियां बदलने लगीं। हर नई तकनीक की अपनी कुछ खासियत होती है और इसके साथ ही वह अपना चरित्र भी विकसित करती है। रील्स का जो चरित्र विकसित हुआ है, उसमें स्थलापन ज्यादा है, गंभीरता कम है। इसे समझने के लिए छाप्रा यानी प्रेस से मीडिया तक की यात्रा को गंभीरता से देखना और समझना होगा। रेडियो के आविष्कार और फिर टेलीविजन के विस्तार के पहले तक पत्रकारिता की बुनियाद में छापेखाने ही रहे। शुरूआती दौर में पत्रकारिता को प्रेस इसी मध्यम के किंचित गुणों के साथ उसकी पहचान के साथ प्रेस जुड़ा रहा, उसके प्रति विशिष्टताबोध बना रहा। टेलीविजन के विस्तार और बजरिए इंटरनेट माध्यमों की आवाजाही ने इस विशिष्टताबोध युक्त पहचान को मीडिया में रूपांतरित कर दिया है। इस यात्रा में मोटे तौर पर पत्रकारिता के दो रूप दिखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से जन्मे छापे की पत्रकारिता को में मिले संस्कारों को अब तक कमोबेश अपनाए रखा है। बाद में आए रेडियो और टीवी में तकनीक भले ही प्रधान रहा,लेकिन उनके मूल में भी छापे की ही पत्रकारिता रही। इसके बावजूद तकनीक प्रधान और अत्याधुनिक माध्यम टीवी छापे की बुनियादी मूल्यों से काफी दूर दिखता है।

उदंत मार्टंड के प्रकाशक और संपादक जुगल किशोर शुक्ल हों या बंगाल गजट निकालने वाले जेम्स ऑगस्टस हिक्री, उन्हें अखबार निकालने का गहरा युगबोध था। लेकिन उन्हें पता था कि वह जो कार्य करने जा रहे हैं, वह बेहद दुष्कर है। उनके सामने संसाधनों की ही चुनौतियां ही नहीं

थी, पाठक जुटाना और अपने छापे की बात उन तक पहुंचाना भी आसान नहीं था। उन्हें आभास था कि उनकी खरी बातों को तत्कालीन विदेशी सत्ता स्वीकार नहीं करेगी। संसाधनों के अभाव और सरकारी सहयोग नहीं मिलने की वजह से ही उदंत मार्टंड असमय कालकवलित हो गया। उसे संसाधन या सरकारी सहयोग इसलिए नहीं मिले, क्योंकि उसका स्वर भारतोन्मुखी था, वह हिंदी समाज के हित के हेत निकल रहा था, उसे भारतीय मूल्यों की चिंता थी और भारतीय समाज के नवजागरण में वह भागीदार बनना चाहता था। यह कहानी उदंत मार्टंड तक ही सीमित नहीं रही। बाद के दिनों में भी हिंदी में तमाम समाचार पत्र निकले और बंद होते रहे। इस लिहाज से कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास नवजागरण का ही इतिहास नहीं है, अखबारों के निकलने और बंद बंद होने के सिलसिले का भी

आए, पुराने माध्यम के ख़ात्मे की आशंका जताई जाती रही। हालांकि नए माध्यम के किंचित गुणों के साथ प्रतियोगिता और साम्यता बरतते हुए पुराने माध्यम ने जहां खुद को ज्यादा प्रतियोगी बनाया। हर नए माध्यम के अवतार और विकास के मूल में नई तकनीक रही है। तकनीक की एक विशेषता है, हर नई तकनीक हमेशा पुरानी के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होती है। इस लिहाज से छापे के बाद आए रेडियो ने लोगों को ज्यादा लुभाया। लेकिन रेडियो के साथ प्रतियोगिता में छापे ने हार नहीं मानी और उसके बरक्स खुद को भी पहले तुलना में ज्यादा गतिमान बनाया, अपने कंटेंट और प्रस्तुति में विविधता और नवीनता की खोज की। इसके बाद अखबारों का प्रसार बढ़ा, रेडियो को तो वैसे ही अपनी नई तकनीक के चलते आगे बढ़ना ही था।

जब टेलीविजन ने मीडिया की दुनिया में



इतिहास है। लेकिन इस सिलसिले में भी समानता दिखती है, पत्रों का मूल उद्देश्य भारतीय मूल्यों, स्वाधीन सोच के लिए जागरण पैदा करना और राष्ट्र हित पर खुद को तिरोहित करना ज्यादातर पत्रों के प्रकाशन के मूल में दिखता है। कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के जिन यानी गुणसूत्र में तिरोहित होने का ही भाव रहा है। यही वजह है कि हिंदी पत्र खतरा उठाते हुए भारतीयता की बात करना और सार्वजनिक हित का सवाल उठाना अपना पुनीत कर्तव्य मानते रहे।

बेशक आज के समाचार पत्र भी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सवालों में आना सिर्फ अखबारी संस्थानों और उनके कर्तव्यताओं की सोच का ही मसला नहीं है, बल्कि उदारीकरण के बाद बढ़ी अर्थप्रधानता और पूंजी के खेल से उपजी मजबूरी भी है। फिर भी जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ जिन मूल्यों को भारतीय समाज ने स्वीकार किया और आत्मसात किया है, उन्हें अब भी अखबारों ने ही आत्मसात कर रखा है। इनकी तुलना में टीवी की पत्रकारिता कहीं ज्यादा चंचल और चलायमान नजर आती है।

पत्रकारिता के जब भी नए माध्यम सामने

अगले चरण के रूप में कदम रखा, दोनों पुराने माध्यमों के ख़ात्मे की आशंका जताई जाने लगी। हालांकि कोई ख़त्म नहीं हुआ, रेडियो ने खुद के लिए नई तकनीक यानी फ़्रीक्वेंसी मॉड्युला यानी एफएम की ईजाद कर ली और अपने लिए जीवन की नई राह खोज ली तो अखबारों ने अपने पत्रे टेलीविजन के पर्दे की तरह चमकादार और दृश्यवान बनाने लगे। अखबारों पर विजुअल का प्रभाव फोटो और चित्रों के विस्तार के रूप में दिखा। इसके असर से अखबार अब भी बचे हुए हैं, रेडियो भी जिंदा है और टेलीविजन भी विस्तृत हो चुका है। लेकिन जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, जिसमें एक पर्दा होता है, उसे चुनौती रील्स और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो माध्यमों से मिल रही है। टेलीविजन को पहले इंटरनेट से चुनौती मिली, लेकिन बाद के दिनों इंटरनेट ने खुद में मीडिया के हर फॉर्मेट को समाहित कर लिया। इसी बीच रील्स और टिकटैक जैसे शॉर्ट फॉर्मेट आ गए और टेलीविजन को भी चुनौती मिलने लगी।

मीडिया के शुरूआती दोनों माध्यम जहां मूल्यों और संघर्ष की कशमकश वाले दौर में पैदा हुए, पले और बढ़े, इसलिए उनके चरित्र पर मूल्यों और संघर्ष का असर दिखता है। लेकिन

असर यह हुआ कि उन्होंने गंभीरता की बजाय दृश्यों के लिए माकूल नाटकीयता को अपनाया, उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों की बजाय पारसी नौटंकी शैली को संवाद अदायगी और नाटकीयता पर जोर दिया। आज यह नाटकीयता ही भारतीय टेलीविजन की मुख्यधारा है। हालांकि जिन देशों में टीवी भारत की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित हुआ, जहां उसका आविष्कार हुआ, वहां टेलीविजन की पत्रकारिता पर छापे की पत्रकारिता जैसी गंभीरता दिखती है, वहां के खबरिया टीवी के पर्दे नाटकीयता से युक्त नहीं हैं। भारतीय परिदृश्य में एक और तथ्य को भी याद रखा जाना चाहिए। टीवी में बड़ी पूंजी लगती है, इसलिए इस पूंजी की वापसी की गारंटी भी चाहिए होती है, नाटकीयता इस वापसी में सनसनी को भी हथियार बना लिया है। चूंकि यह दृश्य प्रधान माध्यम है, इसलिए यहां गंभीरता और गुणों पर नहीं, खूबसूरत और प्रभावी दृश्यों पर जोर है। रील्स ने इसे और बढ़ावा ही दिया है।

देश में अब जीवन, श्रम और बुनियादी ढांचे को एक साथ चुनौती दे रही है गर्मी

असल में गर्मी कितनी बढ़ी है, यह जानने के लिए 1981-2024 के जलवायु आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच ‘क्रेविस’ पर उपलब्ध है। इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पहला, प्रत्येक चार में से तीन भारतीय ऐसे राज्यों में रहते हैं, जहां हर साल भीषण गर्मी का खतरा बना रहता है। दूसरा, बहुत अधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत अधिक गर्म रातों की संख्या इससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह खासतौर पर घनी आबादी वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है।

(शालू अग्रवाल) गर्मी लोगों के जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रही है। अब तक ग्यारह से अधिक राज्य इसे राज्य आपदा घोषित कर चुके हैं। सोलहवें वित्त आयोग ने भी लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सुझाव दिया है। इस समय उत्तर और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में है। कई जगहों पर तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। भारत जैसे देश के लिए गर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारा रिश्ता अब बदल रहा है। ऐसा इसलिए है कि इसानों ने वैश्विक जलवायु को बदल दिया है। बीते दस साल पूरी दुनिया में अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। हमने अपने आसपास की जलवायु को भी बदल दिया है। हमने अपने घर और शहर बनाने का तरीका, अपनी जीवनशैली और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को भी बदल दिया है। इसकी वजह से बढ़ती गर्मी के हिसाब से खुद को ढालना अब हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया है। असल में गर्मी कितनी बढ़ी है, यह जानने के लिए 1981-2024 के जलवायु आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच ‘क्रेविस’ पर उपलब्ध है। इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पहला, प्रत्येक चार में से तीन भारतीय ऐसे राज्यों में रहते हैं, जहां हर साल भीषण गर्मी का खतरा बना रहता है। दूसरा, बहुत अधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत अधिक गर्म रातों की संख्या इससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह खासतौर पर घनी आबादी वाले जिलों और शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। वर्ष 2010 में दिल्ली में जहां हर साल सोलह बहुत गर्म रातें होती थीं, वहीं उच्च उत्सर्जन की स्थिति में वर्ष 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष इक्यावन हो सकती है। इसका इसान के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर

प्रभाव पड़ता है। शरीर और शहर, दोनों को रात के वक्त दिन की गर्मी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे वातानुकूलन या ठंडक देने वाली सुविधाओं के बगैर कम हवादार इमारतों में रहने या इन्में काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तीसरा, गर्मी के मौसम में उमस (आर्द्रता) बढ़ रही है। ऐसा उत्तर भारत और सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में विशेष रूप से देखा जा रहा है। ग्यारह से अधिक राज्य इसे राज्य आपदा घोषित कर चुके हैं: गर्मी लोगों के जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रही है। अब तक ग्यारह से अधिक राज्य इसे राज्य आपदा घोषित कर चुके हैं। सोलहवें वित्त आयोग ने भी लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का सुझाव दिया है। इस ‘मूक आपदा’ का प्रभावी तरीके से सामना करने में चार कदम उपयोगी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, शहरी प्रशासकों को गर्मी का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनानी होंगी। गर्मी का असर सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता है। यह स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होता है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाना बहुत जरूरी है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र का ठाणे नगर निगम है, जहां पिछले दो वर्षों से ‘हीट एक्शन प्लान’ लागू है। यह योजना बताती है कि गर्मी से बचाव के लिए कब, कहाँ और कैसे कदम उठाना। इसके तहत ऐतिहासिक जलवायु आंकड़ों का अध्ययन करके गर्मी के जोखिम का पता लगाया गया और फिर उसके आधार पर अलग-अलग वार्डों को चिह्नित किया गया। इसके अलावा, महसूस होने वाली गर्मी और रात्रिकालीन तापमान के आधार पर प्रत्येक वार्ड में स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी जारी करने के लिए तापमान की सीमा

भी तय की गई। ठाणे शहर में इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का एक संयुक्त कार्यबल बनाया गया है। इसके पास अलग से बजट भी है। लू चलने पर यह कार्यबल सुनिश्चित करता है कि ठाणे शहर में निशुल्क प्याऊ लगाए जाएं, अधिक भीड़-भाड़ वाले चौकों, जहां पर लोगों को यातायात संकेतकों की वजह से देर तक रुकना पड़ता है, वहां ‘हरित छांव’ की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए वार्ड स्तर पर गर्मी से बचाव के उपायों पर जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है। ऐसी कार्ययोजना को भीषण गर्मी की चुनौती से जूझ रहे सभी शहरों में लागू करने की जरूरत है। दूसरा, सभी कारोबारों को अपने व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं में गर्मी से बचाव को शामिल करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2030 तक गर्मी और उमस के कारण लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, यानी कार्मकाजी घंटों का नुकसान होगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 फीसद के बराबर नुकसान हो सकता है। वर्ष 2025 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और नियोक्ताओं को परामर्श जारी किया था। इसमें श्रमिकों, खासतौर पर खुले स्थान पर और कठिन परिश्रम करने वालों को गर्मी से बचाने वाले उपायों को लागू करने के लिए कहा गया था। गर्मी से न केवल श्रमिकों की सेहत, बल्कि मशीनों की कार्यक्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और पानी तथा ऊर्जा का बजट भी प्रभावित होता है। कई भारतीय कंपनियों ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसमें गर्मी के खतरे से ज्यादा प्रभावित लोगों की पहचान की गई है। आराम के लिए छायादार जगह बनाने, लगातार पानी पीते रहने का नियम और काम करने की पोलियों में बदलाव लागू किए गए हैं। ऐसे प्रयासों को तत्काल बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है।

तीसरा, बिजली कंपनियों को अपने बिजली संयंत्र और नेटवर्क को गर्मी से सुरक्षित बनाना होगा। भीषण गर्मी से बचाव में भरोसेमंद और किफायती बिजली आपूर्ति की अहम भूमिका है। हर साल लू चलने के साथ लोग बड़ी संख्या में एसी और कूलर खरीदते हैं। गर्मी, उमस और बिजली में नई मांग आने के कारण विद्युत वितरण नेटवर्क और ट्रांसफार्मर पर अचानक बोझ बढ़ जाता है। वर्ष 2025 में अत्यधिक बोझ और नमी आने के कारण लगभग दस फीसद, यानी तेरह लाख ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे। इसके समाधान के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं- पहला, बिजली कंपनियों को अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को पहले से मजबूत करना चाहिए। दूसरा, बिजली कंपनियों को बिजली की मांग का आकलन करते समय रात के समय के अधिक तापमान और एसी के अधिक इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, बिजली की बहुत अधिक मांग एक साथ न आए, इसके लिए अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग बिजली दरों की व्यवस्था को लागू करने जैसे सुधार करने चाहिए। चौथा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से भी बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारों को सार्वजनिक और निजी निवेशों को गर्मी से बचाव के उपायों की दिशा में ले जाना होगा। साथ ही, गरीब और कमजोर वर्गों, फसलों, पशुओं, जंगलों और घरों, स्कूलों व अस्पतालों को लंबी गर्मी से बचाने के उपाय भी खोजने होंगे। प्रत्येक सरकारी योजना में गर्मी से बचाव की रणनीति को शामिल कर इसकी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन व्यापक समाधानों को पाने के लिए निजी निवेश को शोध और विकास के साथ-साथ तापरोधी फसलों, निर्माण सामग्री और ऊर्जा कुशल शीतलन तकनीकों के व्यवसायीकरण की दिशा में मोड़ना होगा।

की भागीदारी रही। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध पूर्णिमा तेलम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल, कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

